www.adbhutsamachar.com

अद्भुत समाचार

वर्ष – 15 | अंक–39 | RNI-No. : UPHIN/2011/43806 | लखनऊ,बुधवार 07 जनवरी, 2026 | प्रातः कालीन संस्करण | (हिन्दी दैनिक) | पृष्ठ–4 | मूल्य 1 रुपया

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर सीएक्यूएम को लगाई फटकार, कहा- कर्तव्य निभाने में रहे असफल

नयी दिल्ली (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली–एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को कर्तव्य निभाने में असफल रहने पर फटकार लगाई है। वहीं सीएक्यूएम की दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद टोल प्लाजा को हटाने या अस्थायी रूप से बंद करने की मांग को ठुकरा दिया है। मंगलवार को शीर्ष अदालत में सुनवाई के दौरान वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) दिल्ली बॉर्डर पर टोल प्लाजा को अस्थायी रूप से बंद करने या हटाने के मुद्दे पर 2 महीने का समय मांगा था। जिस पर फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को ठुकरा दिया और कहा कि आयोग अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा है। वहीं अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को चरणबद्ध तरीके से लंबे समय के समाधानों पर विचार करना शुरू करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह विभिन्न हितधारक के रुख से प्रभावित हुए बिना टोल प्लाजा के मुद्दे पर विचार करेगा। इसी के साथ दो हफ्ते में विशेषज्ञों की बैठक बुलाने और बढ़ते प्रदूषण के मुख्य कारणों पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और

पूर्वी चंपारण पहुंचा विश्व का सबसे बड़ा सहस्त्र शिव लिंगम

17 जनवरी को होगी स्थापना

नयी दिल्ली (एजेंसी)मोतिहारी तमिलनाडु में महाबलीपुरम के पट्टीकाडु से 47 दिनों पूर्व चला विश्व का सबसे बड़ा सहस्त्र शिव लिंगम 2225 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर बिहार में पूर्वी चंपारण के कैथवलिया पहुंच चुका है। मंदिर परिसर में 18 फीट ऊंचा पेडेस्टल एवं लगभग 15 फीट आधार संरचना पर 17 जनवरी 2026 को सहस्त्र शिव लिंगम की स्थापना होगी। इस सहस्त्र शिव लिंगम को तमिलनाडु में महाबलीपुरम के पट्टीकाडु गांव में एक ही काले ग्रेनाइट पत्थर से 10 वर्षों में तराशा गया है। 33 फीट ऊँचा और 210 मीट्रिक टन (210,000 किलोग्राम) वजनी सहस्त्र शिव लिंगम को 21 नवंबर 2025 को 96 चक्के वाले विशेष ट्रक पर लाद कर महाबलीपुरम से बिहार के कैथवलिया, विराट रामायण मंदिर के लिए रवाना किया गया था, जो मंगलवार 06 जनवरी 2026 को 47 वें दिन सफलतापूर्वक कैथवलिया पहुंचा। विनायक वेंकटरमण की कंपनी के वास्तुकार लोकनाथ के अथक परिश्रम से तैयार सहस्त्र शिव लिंगम पर छोटे छोटे 1008 शिवलिंग की आकृतियां उकेरी गयीं हैं। महावीर मंदिर ट्रस्ट, पटना के तहत निर्मित किए जा रहे इस विराट रामायण मंदिर के ट्रस्टी शायन कुणाल ने बताया कि, सहस्त्र शिव लिंगम मंदिर परिसर में पहुंच चुका है। 17 जनवरी 2026 को वैदिक अनुष्ठान के साथ धर्माचार्यो द्वारा इसे 18 फीट ऊँचे पेडेस्टल और 15 फीट की आधार संरचना पर अधिष्ठापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस लिंगम के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि बाद में निर्धारित की जाएगी। आचार्य शिवानन्द ब्रह्मचारी उर्फ वांचस्पति मिश्र ने सहस्त्र शिव लिंगम के महात्म्य के बारे में बताया कि सहस्त्र शिव लिंगम का अर्थ है हजारों शिव लिंग, जो भगवान शिव के अनंत रूप, ब्रह्मांड की विशालता, और उनकी निराकार प्रकृति का प्रतीक है। यह सहस्रनाम की तरह शिव के विभिन्न गुणों और रूपों को दर्शाता है, जहां सहस्र का मतलब हजार होता है और लिंग स्वयं सृजन, शक्ति और परम सत्य का प्रतीक है, जिसमें ब्रह्मांड समाया है।उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण बिहार के लिए यह गौरवशाली क्षण है, जब हम अपने अराध्य देवाधिदेव श्री महादेव को एक साथ सहस्त्र रूप में चंपारण की पावन भूमि पर अधिष्ठापित होते हुए देख रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और महावीर मन्दिर, पटना साहित कई संस्थानों के संथापक रहे स्व. आचार्य किशोर कुणाल ने चंपारण के कैथवलिया में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर की स्थापना का सपना देखा था।उन्होंने अपने जीवन काल में ही भूमि अधिग्रहण के साथ मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया था। संयोगवश मंदिर निर्माण पूर्ण होने से पूर्व ही उनका निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शायन कुणाल ने निर्माण की पूरी जिम्मेवारी उठायी और निर्माण की निरन्तता को जारी रखा। इस विराट मंदिर का आकार भी बेहद भव्य होगा। यह मंदिर 1080 फीट लंबा, 580 फीट चौड़ा एवं 270 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है। कुल 123 एकड़ में फैले मंदिर के परिसर में 22 मंदिर और 18 शिखरों का निर्माण होगा, जिसे 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

एक्टर विजय की सियासी मुश्किलें बढ़ीं

करूर भगदड़ केस में सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया

नयी दिल्ली (एजेंसी)केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेता–राजनेता और तमिलगा वेट्री कजगम (टीवीके) के संस्थापक विजय को करूर भगदड़ मामले में पूछताछ के लिए 12 जनवरी को नई दिल्ली स्थित एजेंसी मुख्यालय में तलब किया है। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। 27 सितंबर को तमिलगा वेट्री कजगम प्रमुख विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। सीबीआई ने 26 अक्टूबर को भगदड़ की जांच अपने हाथ में ले ली। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने इस मामले में तमिलगा वेट्री कजगम के कई पदाधिकारियों से पूछताछ की है।इससे पहले 27 अक्टूबर को, विजय ने महाबलीपुरम के एक रिसॉर्ट में पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की, ठीक एक महीने बाद जब यह घातक भगदड़ हुई थी। विजय और उनकी पार्टी ने करूर भगदड़ पर बार–बार दुख व्यक्त किया है और इस घटना में अपनों को खोने वाले परिवारों को 20 लाख रुपये देने का वादा किया है। इसके अलावा, घायलों को भी 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। पार्टी ने यह राशि परिवारों के खातों में जमा भी कर दी है। टीवीके ने ग पर पोस्ट किया, ष्39 परिवारों को 20–20 लाख रुपये भेजे जा चुके हैं कुल मिलाकर 7.8 करोड़ रुपये।ष्

पुलिस के अनुसार, घटना के समय वेलुसामीपुरम में पुलिस क्वार्टर के पास टीवीके द्वारा व्यवस्थित की गई एम्बुलेंस सहित लगभग पांच एम्बुलेंस तैनात थीं। 28 सितंबर को, एडीजीपी (कानून और व्यवस्था) डेविडसन देवसिरवथम ने पत्रकारों को बताया कि भगदड़ के तुरंत बाद, पुलिस ने माइक्रोफोन के माध्यम से स्थानीय थाने को सूचित किया और अमरावती अस्पताल से लगभग 10 एम्बुलेंस सेवा में लगाई गईं। इससे पहले, पुलिस ने कहा था कि रैली में27,000 लोग शामिल हुए, जो अपेक्षित 10,000 प्रतिभागियों की संख्या से लगभग तीन गुना अधिक थे, और त्रासदी के लिए विजय के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने में सात घंटे की देरी को जिम्मेदार ठहराया था।

मिशन कर्मयोगी: सभी अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग अनिवाय:सीएम योगी

लखनऊ।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ‘मिशन कर्मयोगी’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक परिवर्तनकारी पहल है, जिसका उद्देश्य सरकारी तंत्र को अधिक सक्षम, दक्ष और जनोन्मुखी बनाना है।मुख्यमंत्री ने ‘मिशन कर्मयोगी’ के तहत प्रदेश में अब तक हुई प्रगति और आगामी कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार कर उन्हें आईगॉट (पळब्ज) कर्मयोगी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करें।

सीएम योगी ने कहा कि विभागों और सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) और साइबर सिक्योरिटी को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि अधिकारी एवं कर्मचारी बदलती तकनीकी चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को अपडेट कर सकें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रदेश के सभी ट्रेनिंग सेंटर्स कैपेसिटी बिल्डिंग से जुड़े पाठ्यक्रम अवश्य तैयार करें।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए सात दिवसीय कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम को अनिवार्य किया जाए, जिससे कार्यकुशलता, निर्णय क्षमता और सेवा वितरण में और अधिक सुधार हो सके।

समीक्षा बैठक में बताया गया कि आईगॉट कर्मयोगी के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। अब तक प्रदेश के 18.8 लाख से अधिक कार्मिक इस प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके हैं, जो वर्ष 2025 में देश भर में हुई कुल ऑनबोर्डिंग का लगभग 93 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि मिशन कर्मयोगी का वास्तविक लाभ शासन और आम जनता तक पहुंचे।

राष्ट्रपति मुर्मू का आदेश, अब Union Territories में प्रशासक लागू करेंगे इंडस्ट्रीयल रिलेशन कोड

इस कदम का उद्देश्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत जारी किया गया है और 16 जनवरी, 2023 और 22 जून, 2023 को जारी की गई पिछली अधिसूचनाओं का स्थान लेता है।

नयी दिल्ली (एजेंसी)राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों और उपराज्यपालों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अंतर्गत ष्उपयुक्त सरकारष् की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने के लिए अधिकृत किया है। इस कदम का उद्देश्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम कानूनों के कार्यान्वयन में स्पष्टता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के तहत जारी किया गया है और 16 जनवरी, 2023 और 22 जून, 2023 को जारी की गई पिछली अधिसूचनाओं का स्थान लेता है।हालांकि, गृह मंत्रालय द्वारा 2 जनवरी को जारी की गई नई अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि पिछली अधिसूचनाओं के अंतर्गत पहले से की गई या छोड़ी गई कार्रवाइयां अप्रभावित रहेंगी, जिससे निरंतरता और कानूनी निश्चितता बनी रहेगी। अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के प्रशासक या उपराज्यपाल, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के तहत उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में और अधिसूचना संख्या एस.ओ. 273(ई), दिनांक 16 जनवरी, 2023, एस.ओ. 2750(ई), दिनांक 22 जून, 2023 और एस.ओ. 2752(ई), दिनांक 22 जून, 2023 को निरस्त करते हुए, उन कार्यों को छोड़कर जो ऐसे निरस्तीकरण से पहले किए जाने थे या नहीं किए जाने थे, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निर्देश देते हैं कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश तक, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (35 ऑफ 2020) के तहत उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे और कार्यों का निर्वहन करेंगे, उन क्षेत्रों के लिए जहां उक्त केंद्र शासित प्रदेशों को उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के रूप में कार्य करना आवश्यक है। ये शक्तियां उन क्षेत्रों में लागू होंगी जहां संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों को कानून के तहत उपयुक्त सरकार के रूप में कार्य करना आवश्यक है।

छात्रसंघ चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट लागू वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली (एजेंसी) उच्चतम न्यायालय ने देशभर के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों के लिए नियामक ढांचा निर्धारित करने से जुड़ी 2006 की लिंगदोह समिति रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रही याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के निर्देश पर लिंगदोह समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य कैंपस राजनीति से धन और बाहुबल को खत्म करना और शैक्षिक मानकों को बरकरार रखना था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने शिव कुमार त्रिपाठी नामक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह याचिका विस्तृत सुनवाई योग्य नहीं है। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, त्रिपाठी के वकील ने कहा कि याचिका में लिंगदोह समिति की रिपोर्ट को लागू करने का अनुरोध किया गया है ताकि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनावों को निष्पक्ष बनाया जा सके। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश ने इस याचिका को पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी प्रचार पाने के लिए दायर याचिका करार दिया।

दिल्ली विधानसभा में कुत्तों के मुद्दे पर हंगामा, बीजेपी की मांग- केजरीवाल माफी मांगें

नयी दिल्ली (एजेंसी) दिल्ली विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि स्पीकर को लंच तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा है। बीजेपी नेताओं ने सदन के अंदर अरविंद केजरीवाल माफी मांगो के नारे लगाए जिससे विधानसभा के अंदर माहौल गरमा गया। शिक्षा मंत्री आशीष सूद समेत तमाम विधायकों का कहना है कि केजरीवाल और उनकी पार्टी ने कुत्तों की गिनती के लिए सरकारी टीचरों की नियुक्ति को लेकर झूठ फैलाया और ऐसा कोई सर्कुलर जारी नहीं हुआ है।दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दिल्ली विधानसभा शुरू होने से पहले ही कुत्तों की गिनती के लिए सरकारी टीचरों वाले मामले पर बात की थी। आशीष सूद कल अरविंद केजरीवाल को पत्र भी लिखा था। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही भाजपा विधायक मुखर हो गए। सब सदन के बाहर बैनर लिए नारेबाजी जारी है। कुते के मामले को लेकर झूठ फैलाने के लिए उनसे माफी मांगने को कहा जा रहा है। विधानसभा में केजरीवाल से माफी को लेकर लगातार चल रहे हंगामे की वजह से लंच तक सत्र को स्थगित कर दिया गया है।भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल और आप (आप) गैंग ने झूठ बोला। उन्होंने दावा किया कि हमने कुत्तों से संबंधित कोई आदेश पारित किया था। उन्हें शर्म आनी चाहिए। आज हमने विधानसभा में मांग की कि वे इसके लिए माफी मांगें। हमारी मांग है कि वे दिल्ली से, शिक्षकों से और पूरे देश से माफी मांगें। आशीष सूद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैंने सर्कुलर पढ़कर बताया था। मैंने कहा था कि इस सर्कुलर में अगर कहीं भी शिक्षक के लिए कुत्तों की गिनती के बारे में लिखा हो तो मैं माफी मागूंगा।

वह कोई साक्ष्य नहीं दिखा पाए। उन्होंने इस मुद्दे को उठाना बंद कर दिया है, लेकिन सोशल मीडिया पर सरकार को बदनाम किया जा रहा है इसलिए मैंने उनसे कहा है कि लोगों के बीच इस विषय को लेकर भ्रम न फैलाएं। एक पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया झूठ बोल रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि सरकार प्रदूषण पर चर्चा करने से बच रही है। जबकि विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा होनी है। अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार

सीएम योगी ने पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को दी बड़ी राहत

32,679 पदों पर सभी वर्गों को आयु सीमा में मिलेगी छूट

लखनऊ ,06 जनवरी (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती–2025 के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त तीन साल की छूट देने का निर्णय लिया गया है।इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। सीधी भर्ती–2025 के अंतर्गत कुल 32,679 पदों को भरे जाने के लिए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके मुताबिक आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुषध्महिला), आरक्षी पीएसीध्सशस्त्र पुलिस (पुरुष), आरक्षी विशेष सुरक्षा बल (पुरुष), महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार पुलिस (पुरुष) तथा जेल वार्डर (पुरुष एवं महिला) पदों पर भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को यह आयु छूट एक बार के लिए प्रदान की जाएगी।सरकार ने यह निर्णय उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली–1992 के नियम–3 के आलोक में लिया है। यह फैसला 31 दिसंबर 2025 को जारी भर्ती विज्ञप्ति के अनुक्रम में 5 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के माध्यम से लागू किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा जो आयु सीमा के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे थे।

सरकार का यह कदम साफ संदेश देता है कि प्रदेश की सरकार युवाओं की वास्तविक समस्याओं को समझती है और समाधान के लिए ठोस फैसले लेने से पीछे नहीं हटती।प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को न्यायसंगत अवसर देना, रोजगार के अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराना और प्रशासनिक निर्णयों में संवेदनशीलता बनाए रखना योगी सरकार की कार्यशैली का हिस्सा बन चुका है।

पुलिस भर्ती में आयु सीमा शिथिलीकरण का यह निर्णय न केवल लाखों युवाओं की उम्मीदों को नया बल देगा, बल्कि यह भी दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार में युवाओं का भविष्य नीति निर्धारण के केंद्र में है।

सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, सपोले बिलबिला रहे हैं

जेएनयू कैंपस में मोदी-शाह के खिलाफ नारेबाजी पर बोली भाजपा

नयी दिल्ली (एजेंसी) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्र नेताओं उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत न मिलने के एक दिन बाद छात्रों के एक समूह ने विश्वविद्यालय परिसर में विरोध–प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें जेएनयू परिसर के अंदर इमाम और खालिद को जमानत नहीं मिलने के खिलाफ विरोध–प्रदर्शन दिखाया गया है। इसमें छात्र सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। वहीं इस नारेबाजी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी और वामपंथी संगठनों पर हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि जेएनयू में नक्सलियों, आतंकियों और दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाने वाले लोग हताशा में हैं। क्योंकि नक्सलियों का खात्मा हो रहा है, आतंकियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और दंगाइयों की पहचान अदालत कर चुकी है। कपिल मिश्रा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, ष्सांपों के फन कुचले जा रहे हैं, सपोले बिलबिला रहे हैं। जेएनयू में नक्सलियों, आतंकियों, और दंगाइयों के समर्थन में भद्दे नारे लगाने वाले हताश हैं क्योंकि नक्सली खत्म किए जा रहे हैं, आतंकी निपटाए जा रहे हैं, और दंगाइयों को कोर्ट पहचान चुका है। एक अन्य एक्स पोस्ट में कपिल मिश्रा ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि नक्सली भी मरेंगे और आतंकी भी मारे जाएंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ जेएनयू में की जा रही नारेबाजी से कुछ हासिल होने वाला नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये विवादित नारे जेएनयू में टुकड़े–टुकड़े गैंग द्वारा लगाए गए थे। उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के कुछ नेताओं पर खालिद और इमाम के पक्ष में बयान देकर सभी हदें पार करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी संस्कृति से जुड़े छात्र अब पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। पूनावाला ने दावा किया कि अदालत के फैसले का विरोध करते हुए उदित राज, वृंदा करात, हुसैन दलवई और पृथ्वीराज चव्हाण जैसे कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के कुछ नेताओं ने आरोपियों को श्निर्दोषश बताया है। भाजपा नेता ने कहा कि वीडियो में साफ दिख रहा है कि विरोध–प्रदर्शन में लगाए गये नारों से उन्होंने सभी हदें पार कर दी हैं। उन्होंने आरोप लगाया, ष्ये वही लोग हैं जो नक्सलियों को शहीद कहते हैं।

ईरान के जेन-जेड प्रदर्शनकारियों से अमेरिकी सहानुभूति के वैश्विक मायन

कमलेश पांडे

अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि पहले तो अमेरिका ने इन्हें यानी चीन–भारत को पटाकर और भारत–चीन को परस्पर उलझाकर अपने चिर शत्रु देश रूस को और अधिक कमजोर की कोशिशें की, लेकिन जब वो अपने नापाक इरादों में सफल नहीं हुआ तो इनके पड़ोस में श्भारत विरोधश को हवा दिलवानी शुरू कर दी।ईरान के जेन–जेड प्रदर्शनकारियों से अमेरिकी सहानुभूति के वैश्विक मायने बड़े ही खतरनाक हैं। लिहाजा यदि समय रहते ही एशियाई देश नहीं चेते तो ये सब धीरे–धीरे अमेरिकी साम्राज्यवादी रणनीतियों के सहज शिकार बन सकते हैं। पहले बंगलादेश, फिर नेपाल और अब ईरान में हुए जेन–जेड प्रदर्शन वाकई अमेरिकी डीप स्टेट की उन छिपी हुई मंशाओं को उजागर करते हैं, जिसका उद्देश्य चीन और रूस के सदाबहार मित्र भारत को कमजोर करना है क्योंकि ये दोनों अमेरिका की वैश्विक दादागिरी की राह के सबसे बड़े रोड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि पहले तो अमेरिका ने इन्हें यानी चीन–भारत को पटाकर और भारत–चीन को परस्पर उलझाकर अपने चिर शत्रु देश रूस को और अधिक कमजोर की कोशिशें की, लेकिन जब वो अपने नापाक इरादों में सफल नहीं हुआ तो इनके पड़ोस में श्भारत विरोधश को हवा दिलवानी शुरू कर दी। इसलिए बंगलादेश व नेपाल न सही, लेकिन ईरान में भारत, चीन और रूस को अविलंब हस्तक्षेप करना चाहिए और कथित लोकतंत्र के नाम पर अमेरिकी थानेदारी का कड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिरोध करना चाहिए, अन्यथा अगला नम्बर अब उन्हीं का आएगा।देखा जाए तो ईरान में रोजगार और बढ़ती महंगाई को लेकर बीते पांच दिनों से जारी जेन–जेड के विरोध प्रदर्शनों ने अब हिंसक रूप अख्तियार कर लिया है। लिहाजा, ईरानी सुरक्षा बलों ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, जिसमें अबतक सात प्रदर्शनकारियों के मारे जाने और कइयों के घायल होने की पुष्टि हुई है। वहीं, इससे व्याकुल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट श्एक्सश पर लिखा है कि, श्अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है तो हम बचाने को तैयार हैं।श् वैश्विक कूटनीतिज्ञों का मानना है कि अमेरिकी नेतृत्व द्वारा दिया गया उक्त बयान ईरान में लोकतंत्र की हिफाजत के बहाने वहां लगी आग में घी डालने जैसा है, जो निंदनीय भी है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप भी अब डीप स्टेट के समक्ष घुटने टेक चुके हैं और इसकी तथाकथित कारगुजारियों को बढ़ावा देने लगे हैं, जो वाकई दिलचस्प है।

हालांकि, इस अमेरिकी दुस्साहस पर पलटवार करते हुए ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा कि, श्ईरान की सुरक्षा रेड लाइन है।श् ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी ने कहा कि– श्अमेरिकी और इजराइल प्रदर्शन भड़का रहे हैं। अमेरिकी दखल से अशांति फैल जाएगी, उन्हें अपने सैनिकों की फिक्र करनी चाहिए।श् कहने का तात्पर्य यह हुआ कि यदि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा तो ईरान उसके खाड़ी देशों और अरब देशों में स्थित सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। पिछले वर्ष वह ईरान–इजरायल युद्ध के दौरान ऐसा कर भी चुका है, जिसके बाद घबराहट में अमेरिका ने उस युद्ध को मध्यस्थता करके बंद करवाया था।स्वाभाविक सवाल है कि ईरानी प्रदर्शनकारियों के जिस तरह के उग्र विडियो सामने आए हैं, जहां प्रदर्शनकारी ईरान की सरकारी इमारतों पर पत्थरबाजी करते देखे गए, उसके दृष्टिगत ईरानी सुरक्षा बलों ने सख्त कार्रवाई करके अपने राष्ट्रीय धर्म का पालन किया है। अन्यथा बंगलादेश व नेपाल की तरह वो सुरक्षाकर्मी भी घुटने टेक सकते थे। हालांकि उन्होंने यह सख्ती दो तीन दिन प्रदर्शनकारियों को झेलने के बाद दिखाई है।इसलिए डॉनल्ड ट्रंप का यह कहना कि, श्ईरान का रिवाज मारना है।श् न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। उनकी यह टिप्पणी कि, श्अमेरिका प्रदर्शनकारियों की मदद को आगे बढ़ने के लिए तैयार है।श् प्रथमदृष्टया ईरान के आंतरिक मामलों में खुला हस्तक्षेप है। इससे जाहिर है कि अब वो भी उस डीप स्टेट के हाथों खेलने को अभिशप्त हैं, जिसका विरोध उन्होंने खुद ही अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान किया था। लिहाजा स्वाभाविक सवाल है कि क्या अब्राहम परिवार में एका स्थापित करने की चाह रखने वाले डॉनाल्ड ट्रंप अब ईरान को इस्लामिक देश नहीं मानते हैं और उसे पुनः पारसी देश बनाने की चाल चल रहे हैं, यक्ष प्रश्न है।

ऐसा इसलिए कि अमेरिकी डीप स्टेट एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो संघीय एजेंसियों जैसे सीआईए, एफबीआई और एनएसए के गुप्त नेटवर्क को संदर्भित करता है। यह कथित रूप से चुनी हुई सरकार के समानांतर सत्ता संचालित करता है। जहां तक डीप स्टेट की परिभाषा का सवाल है तो आपको पता होना चाहिए कि यह शब्द 1990 के दशक में तुर्की से उत्पन्न हुआ और अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में लोकप्रिय हुआ। क्योंकि तब ट्रंप ने इसे रूस की जांच और अन्य विपत्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया। सच कहूं तो यह नेटवर्क वित्तीय, औद्योगिक हितों के साथ मिलकर निर्वाचित नेताओं को प्रभावित करता है। ऐसे में स्वाभाविक सवाल है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति इसे क्यों संरक्षण देते हैं? तो इसका माकूल जवाब यह आम व खास धारणा है कि कुछ प्रशासनों (जैसे– जो बाइडन प्रशासन के द्वारा) को डीप स्टेट का संरक्षण प्राप्त होता है क्योंकि यह विदेश नीति और खुफिया कार्यों में स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि, राष्ट्रपति ट्रंप जैसे नेता इसे अपना दुश्मन मानते आये हैं और इसका विरोध करते रहे हैं। यही वजह है कि वर्तमान राष्ट्रपति ट्रंप (2025 में पुनः शपथग्रहण के बाद) कहीं इसे कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं तो कहीं शह देते नजर आ रहे हैं। इससे वह अपने ही उद्देश्य में विफल साबित हुए। आपने देखा होगा कि भारत में विगत तीन पारियों से केंद्रीय सत्ता पर काबिज भाजपा ने भी डीप स्टेट पर मोदी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था, जबकि डीप स्टेट मुख्यतः षड्यंत्र सिद्धांत है। कई अमेरिकी सर्वे में वहां के आधे लोग इसके अस्तित्व में विश्वास करते हैं। कहना न होगा कि डीप स्टेट की अवधारणा मूल रूप से एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो गुप्त शक्तियों के एक नेटवर्क को संदर्भित करता है। इसका आधुनिक इतिहास तुर्की से जुड़ा है, जहां 1990 के दशक में श्डेरिन देवलेटश् (गहरा राज्य) शब्द का इस्तेमाल सेना, खुफिया एजेंसियों और अपराधी तत्वों के गठजोड़ के लिए हुआ। जहां तक इसके उद्भव की बात है तो इसका प्रारंभिक चरण तुर्की में 1990 के दशक के एक सड़क हादसे से लोकप्रिय हुआ, जिसमें एक राजनेता, पुलिस अधिकारी और माफिया डॉन की मौत हुई। इससे कथित गुप्त गठबंधन यानी डीप स्टेट की चर्चा शुरू हुई। फिर अमेरिका में ओबामा प्रशासन के दौरान इसका जिक्र बढ़ा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 से इसे मुख्यधारा में लाकर सीआईए और एफबीआई जैसी एजेंसियों को निशाना बनाया। जहां तक अमेरिकी संदर्भ में इसके विकास की बात है तो ट्रंप के पहले कार्यकाल में डीप स्टेट को रूस की जांच और अन्य घटनाओं से जोड़ा गया। 2017–18 के सर्वे में लगभग आधे अमेरिकियों ने इसके अस्तित्व में विश्वास जताया। कुछ सिद्धांतकार इसे रोथ्सचाइल्ड, रॉकफेलर जैसे वित्तीय समूहों से जोड़ते हैं, जो 18वीं सदी से बैंकिंग के माध्यम से प्रभाव डालते रहे। जहां तक डीप स्टेट के वैश्विक प्रसार की बात है तो यह तुर्की से निकलकर यह मिस्र, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में फैला। भारत में भाजपा ने 2024 में इसे मोदी सरकार के खिलाफ साजिश से जोड़ा। हालांकि, कतिपय विद्वान इसे अतिशयोक्तिपूर्ण सिद्धांत मानते हैं क्योंकि वो खुद किसी न किसी रूप में डीप स्टेट से लाभान्वित हैं। वास्तव में डीप स्टेट एक षड्यंत्र सिद्धांत है जो सरकारी, सैन्य, खुफिया एजेंसियों और कॉर्पोरेट अभिजात वर्ग के गुप्त नेटवर्क को संदर्भित करता है। यह नेटवर्क लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के बाहर काम करता है और नीतियों को प्रभावित करने का दावा किया जाता है।मसलन, डीप स्टेट शब्द तुर्की के श्डेरिन देवलेटश् से लिया गया है, जो गैर–निर्वाचित तत्वों के समूह को दर्शाता है। अमेरिकी संदर्भ में, यह ब्, थ्ठ७, छै। जैसी एजेंसियों को लक्षित करता है जो कथित रूप से राष्ट्रपति के फैसलों को बाधित करती हैं। यह समूह अपने विशेष हितों, जैसे सुरक्षा या आर्थिक एजेंडे, को आगे बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से सक्रिय रहता है। वहां का पेंटागन, हथियार निर्माता कंपनियां, नौकरशाही और वित्तीय अभिजात यानी बड़े कॉर्पोरेट्स, बैंकिंग समूह जैसे रॉकफेलर या रोथ्सचाइल्ड भी इससे जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, गूगल, फेसबुक जैसे टेक दिग्गज और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे एनजीओ भी इसके पार्ट समझे जाते हैं। नौकरशाह और पूर्व अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, खुफिया अधिकारी जो वैचारिक प्रतिबद्धताओं से प्रेरित रहते हैं, इसके अंग बन हैं। वहीं वहां के

वित्तीय परिवार जैसे रोथ्सचाइल्ड, रॉकफेलर जैसे समूह, जो बैंकिंग और परोपकार के माध्यम से प्रभाव डालते हैं। वहां की सिविल सोसायटी यानी मीडिया, प्रोफेसर, कलाकार और एनजीओ कार्यकर्ता जो मानवाधिकार या पर्यावरण के नाम पर सक्रिय रहते हैं। इसके संचालन का तरीका भी गजब है। ये समूह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बायपास कर शासन परिवर्तन या अस्थिरता पैदा करते हैं। भारत में इन्हें अर्बन नक्सल या राष्ट्रविरोधी इकोसिस्टम से जोड़ा जाता है। यह लोकतांत्रिक नियंत्रण से बाहर रहता है और निर्वाचित नेताओं को कमजोर करने का आरोप लगाया जाता है। हालांकि, कई विशेषज्ञ इसे अतिशयोक्तिपूर्ण सिद्धांत मानते हैं।

बताया जाता है कि अमेरिका के आर्थिक और कॉर्पोरेट हित डीप स्टेट के सिद्धांत में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जहां इन्हें गुप्त नेटवर्क का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। ये हित सरकारी नीतियों को प्रभावित कर लाभ कमाते हैं। वहां से कॉर्पोरेट जुड़ाव रखने वाले यानी कॉर्पोरेट दिग्गज जैसे गूगल, फेसबुक और हथियार कंपनियां डेटा गोपनीयता, कराधान तथा बाजार विनियमन पर प्रभाव डालती हैं। ये शक्तिशाली इकाइयां खुफिया एजेंसियों के साथ साझेदारी कर आर्थिक नीतियों को आकार देती हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जैसे संगठन शासन परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। इसका आर्थिक प्रभाव निर्णायक होता है। वहां के वित्तीय परिवार जैसे रोथ्सचाइल्ड और रॉकफेलर बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण के माध्यम से प्रमुख घटनाओं जैसे एशियाई वित्तीय संकट को प्रभावित करते हैं। ये समूह मुक्त बाजार, व्यापार वार्ता और शॉक थेरेपी जैसी नीतियों को प्रोत्साहित कर विकासशील देशों में बाजार पहुंच सुनिश्चित करते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे उदाहरण स्टॉक बाजार अस्थिरता पैदा करते हैं। ये परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। ये हित सैन्य–औद्योगिक परिसर के साथ मिलकर युद्ध अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं, जहां कॉर्पोरेट फंडिंग राजनीतिक प्रभाव खरीदती है। भारत जैसे देशों में एनजीओ वित्तपोषण कोयला परियोजनाओं का विरोध करता है, जो जीडीपी वृद्धि को 2–3: नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इनके कारनामों से शेष दुनिया के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि गरीब व विकासशील देशों के धनलोलुप नेता व चतुरसुजान अब इनके अंग बन चुके हैं। भारत, चीन व रूस में भी इनकी अच्छी खासी तादात होने की अटकलें हैं।

सम्पादकीय

वेनेजुएला पर हमला

पिछले लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी हमले के बाद गिरफ्तार करना निस्संदेह, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी का दुर्लभ उदाहरण है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन होने तक वाशिंगटन इस लैटिन अमेरिकी देश का संचालन करेगा। यह एक खतरनाक परंपरा है, जिसकी पुनरावृत्ति अमेरिकी महाद्वीप से बाहर होने की आशंका भी बलवती हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि निकोलस मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला में मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से मादुरो को लगातार खलनायक बनाने की कोशिशों में एक वैश्विक तंत्र लगा हुआ था। वैसे आरोप मादुरो पर लगे कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया, असहमतियों को कुचला और लाखों लोगों को निर्वासन के लिये मजबूर किया। उन पर चुनाव में धांधली और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन वैश्विक कूटनीति के जानकार मानते हैं कि ट्रंप के इस दांव का लक्ष्य तानाशाही के पीड़ितों को न्याय दिलाने या इस देश की संप्रभुता की रक्षा के बजाय वेनेजुएला के समृद्ध तेल भंडारों पर नियंत्रण हासिल करना ज्यादा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा सैन्य अभियान चलाकर देश से बाहर किसी शासनाध्यक्ष को गिरफ्तार करना तथा वहां की सत्ता को वाशिंगटन से संचालित करना निश्चय ही साम्राज्यवादी सोच का ही पर्याय है। निस्संदेह, इस अमेरिकी निरंकुशता के गहरे भू–राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे। यहां तक कि मादुरो का विरोध करने वाले अमेरिका के सहयोगी देश भी, अब मुखर होकर चेतावनी देने लगे हैं। रूस और चीन इस अमेरिकी कार्रवाई को नियम–कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिये खतरा बता रहे हैं। वहीं वेनेजुएला के इस घटनाक्रम ने चीन को अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर अमेरिकी आलोचना को बेअसर करने का भरपूर मौका दे दिया है। जिससे ताइवान की चिंताएं बढ़ सकती हैं। अमेरिका के इस कृत्य ने इराक और अफगानिस्तान में हमले व सेना की तैनाती की यादें ताजा कर दी हैं। ऐसे युद्ध जो अमेरिकी आत्ममुग्धता और अति–आत्मविश्वास से शुरू हुए, लेकिन उनका समापन अपमानजनक विदाई से हुआ। लेकिन इन हमलों के बाद वे देश कभी सामान्य नहीं रह पाए। वहीं ट्रंप की यह दलील कि मादुरो को पकड़ने के लिये चलाए अभियान का खर्च वेनेजुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, उसके प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी नियंत्रण की मंशा को ही दर्शाता है। वहीं अमेरिका ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सुशासन, सुरक्षा के लिये वेनेजुएला की जनता की आकांक्षाओं वाले किस नेता को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। भारत भी उन देशों में शामिल है, जिन्होंने घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। जो सही मायनों में भविष्य की वैश्विक चिंताओं के अनुरूप ही है। बहरहाल, देर–सवेर ट्रंप को अहसास होगा कि एक निरंकुश शासक को हटाना आसान है, लेकिन उस देश में दीर्घकालिक शांति–स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये गंभीर प्रयासों की जरूरत होती है।

जर्मन के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की पहली भारत यात्रा

जनवरी 2026 की शुरुआत भारत–यूरोप संबंधों के लिए कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12–13 जनवरी को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय(एम ई ए) के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर मर्ज अहमदाबाद और बेंगलुरु का दौरा करेंगे। यह यात्रा न केवल भारत–जर्मनी द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा देगी, बल्कि भारत और यूरोप के बीच बढ़ते रणनीतिक संवाद को भी रेखांकित करती है।चांसलर मर्ज 12 जनवरी को अहमदाबाद पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी उनका स्वागत करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत–जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा होगी। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच यह रणनीतिक साझेदारी पिछले वर्ष 25 साल पूरे कर चुकी है। बातचीत में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कौशल विकास और मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों के साथ–साथ रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार, हरित एवं सतत विकास तथा लोगों से लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब यूरोपीय संघ की शीर्ष नेतृत्व यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टाकृभी गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने भारत आने वाले हैं। लगातार हो रही ये उच्चस्तरीय यात्राएं यह संकेत देती हैं कि भारत और यूरोप आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूरोपीय संघ में जर्मनी की अहम भूमिका और भारत के साथ उसके मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को देखते हुए, जर्मनी भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार है।प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर मर्ज की पहली मुलाकात 17 जून 2025 को कनाडा मेंआयोजित जी–7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। उस समय, पहलगाम आतंकी हमले के बाद शुरू हुए 'ऑपरेशन सिंदूर' की पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं ने आतंकवाद को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बताया था। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाइयों के प्रति जर्मनी द्वारा जताई गई एकजुटता और समर्थन के लिए चांसलर मर्ज का आभार भी व्यक्त किया था।

भारत और जर्मनी के बीच मई 2000 से रणनीतिक साझेदारी कायम है, जिसे 2011 में सरकारों के प्रमुखों के स्तर पर अंतर–सरकारी परामर्श (आईजीसी) की शुरुआत से और मजबूती मिली।

दुनियाभर में अपना लट्‌ठ गाड़ने पर क्यों तुले हैं चौधरी ट्रंप? Latin America के देशों में क्यों मची है खलबली?

नीरज कुमार दुबे ।

क्यूबा पर ट्रंप का बयान यह दिखाता है कि अमेरिका अब भी शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर नहीं आया है। क्यूबा को कमजोर बताकर वह यह संकेत देना चाहते हैं कि वेनेजुएला से उसका आर्थिक सहारा टूट चुका है और अब दबाव डालने का सही समय है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि क्यूबा आर्थिक रूप से टूटने के कगार पर है, ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और अगर ईरान में सरकार ने जनता पर दमन तेज किया तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा। यही नहीं वेनेजुएला की राजधानी पर अमेरिकी हमले को लेकर उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हम ही प्रभारी हैं और यह अभियान शांति के लिए था। कोलंबिया को भी ट्रंप ने चेतावनी दी है और भारत को भी रूसी तेल खरीदने पर शुल्क बढ़ाने की धमकी दी है। देखा जाये तो ट्रंप के इन बयानों और कार्रवाइयों ने अमेरिका की आक्रामक विदेश नीति को फिर उजागर कर दिया है। इस बीच, संयुक्त राष्ट्र में भी वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई की वैधता पर बहस तेज हो गई है और दुनिया एक बार फिर दो ध्रुवों में बंटती दिख रही है।

अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसने अपराधी को पकड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि अपराध तय करने का अधिकार किसने दिया। क्या दुनिया में केवल एक ही देश न्यायाधीश है। क्या लोकतंत्र की परिभाषा अब बंदूक की नली से तय होगी। अगर यही नियम है, तो कल किसी और देश की बारी भी आ सकती है। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। जहां ताकतवर देश खुलेआम कमजोर देशों की सरकारें गिराने लगे हैं। आज मादुरो जेल में है। कल कोई और होगा। सवाल यह नहीं कि मादुरो सही था या गलत। सवाल यह है कि क्या दुनिया अब बंदूक के कानून से चलेगी। अगर इसका जवाब हां है, तो यह केवल वेनेजुएला की हार नहीं, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था की हार होगी।यह भी साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति अब धमकी की भाषा बोल रही है। वह हर मंच से खुद को शांति दूत बताने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके कदम लगातार युद्ध और हस्तक्षेप की ओर बढ़ते दिखते हैं। क्यूबा, कोलंबिया और ग्रीनलैंड को लेकर उनकी ताजा धमकियां उस सोच का हिस्सा हैं जिसमें अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का निर्णायक मानता है।

क्यूबा पर ट्रंप का बयान यह दिखाता है कि अमेरिका अब भी शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर नहीं आया है। क्यूबा को कमजोर बताकर वह यह संकेत देना चाहते हैं कि वेनेजुएला से उसका आर्थिक सहारा टूट चुका है और अब दबाव डालने का सही समय है। अमेरिका के लिए क्यूबा सिर्फ एक द्वीप नहीं बल्कि वैचारिक चुनौती रहा है। अगर अमेरिका क्यूबा पर सीधे हमले की कोशिश करता है तो यह लैटिन अमेरिका में भारी अस्थिरता ला सकता है। इससे अमेरिका विरोधी भावनाएं और तेज होंगी और रूस तथा चीन को दखल का नया मौका मिलेगा।वहीं, ट्रंप का कोलंबिया को धमकी देना बताता है कि अमेरिका अब अपने पुराने सहयोगियों को भी नहीं बख्श रहा। वेनेजुएला प्रकरण के बाद लैटिन अमेरिका में हालात पहले ही तनावपूर्ण हैं। कई देश अमेरिकी दबाव से थक चुके हैं। वेनेजुएला पर हमले को क्षेत्र के कई देशों ने संप्रभुता पर हमला माना है। अमेरिका पहले भी चिली, निकारागुआ और पनामा जैसे देशों में दखल देता रहा है। कभी तख्तापलट के जरिए तो कभी आर्थिक प्रतिबंधों से। आज भी वही नीति नए शब्दों में लौट आई है।

दूसरी ओर, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का बयान दरअसल आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दिखाता है। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए सामरिक दृष्टि से अहम है। यहां से रूस और चीन की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। लेकिन किसी क्षेत्र को जरूरत बताकर हथियाने की सोच उपनिवेशवादी मानसिकता का उदाहरण है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर दबाव बढ़ाता है तो यह यूरोप और नाटो के भीतर भी दरार पैदा कर सकता है।

वहीं ईरान को लेकर ट्रंप की चेतावनी यह दिखाती है कि अमेरिका खुद को विश्व का पुलिसमैन मानता है। ईरान के आंतरिक मामलों में इस तरह की धमकी अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना है। यह संदेश दिया जा रहा है कि जो भी सरकार अमेरिका की लाइन से हटेगी उसे बल प्रयोग से सुधारा जाएगा। इससे पश्चिम एशिया में पहले से जारी तनाव और भड़क सकता है।

उधर, भारत के साथ अमेरिका के रणनीतिक संबंधों के बावजूद ट्रंप की धमकियां बताती हैं कि उनकी दोस्ती भी शर्तों पर टिकी है। भारत को रूसी तेल खरीदने पर चेतावनी देकर वह यह साबित करना चाहते हैं कि अमेरिकी हित सर्वोपरि हैं। यह दबाव नीति भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को चुनौती देती है और बताती है कि अमेरिका साझेदारी को बराबरी का नहीं बल्कि नियंत्रण का जरिया मानता है।

हम आपको यह भी बता दें कि वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को दुनिया ने अलग–अलग नजर से देखा है। वेनेजुएला का कहना है कि यह सीधी आक्रामकता है जबकि अमेरिका इसे शांति अभियान बता रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में इस कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठे हैं। कई देशों ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। इस हमले ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ अमेरिका और उसके समर्थक हैं तो दूसरी तरफ वह देश हैं जो संप्रभुता और बहुपक्षीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं।इसके अलावा, वेनेजुएला के बाद लैटिन अमेरिका में अमेरिका विरोधी भावना और मजबूत हुई है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका आज भी मोनरो सिद्धांत के नाम पर पूरे महाद्वीप को अपना हिस्सा मानता है। ट्रंप ने खुद कहा कि यह हमारा गोलार्ध है। यह बयान साफ करता है कि अमेरिका अब भी क्षेत्रीय वर्चस्व की पुरानी सोच से बाहर नहीं निकला है।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नेता रोज शांति की बात करता है और नोबेल शांति पुरस्कार पर अपना दावा करता है वही युद्ध क्यों छेड़ता जा रहा है? इसका जवाब ट्रंप की घरेलू राजनीति में छिपा है। दरअसल आक्रामक राष्ट्रवाद उनके समर्थकों को जोश देता है। हर नया टकराव उन्हें मजबूत नेता के रूप में पेश करता है। शांति उनके लिए लक्ष्य नहीं बल्कि नारा है।

बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति आज धमकी, दबाव और बल प्रयोग का मिश्रण बन चुकी है। क्यूबा, कोलंबिया, ग्रीनलैंड, ईरान, भारत और वेनेजुएला सभी इस नीति के अलग–अलग शिकार हैं। यह रवैया दुनिया को सुरक्षित नहीं बल्कि और अस्थिर बना रहा है। अगर यही सिलसिला चला तो अमेरिका खुद को अलग थलग पाएगा और वैश्विक व्यवस्था और कमजोर होगी। शांति की बात करने वाले हाथों में जब मिसाइल हो तो दुनिया को सतर्क हो जाना चाहिए।

वेनेजुएला संकटः अमेरिकी निरंकुशता और वैश्विक कानूनों का हनन

ललित गर्ग ।

दरअसल, वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिका की असली चिंता न लोकतंत्र है और न ही मानवाधिकार, बल्कि वहां के विशाल तेल भंडार हैं। वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा देश है और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की अमेरिकी भूख कोई नई बात नहीं है।वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में नियम–कानूनों से संचालित होती है या फिर ताकतवर राष्ट्रों की इच्छा ही वैश्विक न्याय का नया मानदंड बन चुकी है। निश्चित तौर पर वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला महाशक्तियों की निरंकुशता को दर्शा ही रहा है, यह वैश्विक कानूनों का अतिक्रमण भी है, जो अमेरिकी दादागिरी का त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण संकेत है, वह केवल लैटिन अमेरिका तक सीमित घटना नहीं है, बल्कि समूची दुनिया के लिये एक खतरनाक मिसाल है। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, उससे जुड़े कूटनीतिक, राजनीतिक और अन्तराष्ट्रीय कानून संबंधी सवाल जो खडेध हुए ही हैं, पर अमेरिका को हस्तक्षेप का अवसर देने के लिये मादुरो की नीतियां भी चर्चा में आई हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की वजहें हो सकती है, लेकिन ट्रंप को यह तो सुनिश्चित करना ही होगा कि यह राष्ट्र अस्थिरता का अड्डा न बन जाये।

अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को वैश्विक शांति का मसीहा घोषित करते नहीं थकते, लेकिन उनकी नीतियां और कार्रवाइयाँ बार–बार युद्ध, हस्तक्षेप और सत्ता परिवर्तन की मानसिकता को उजागर करती हैं। यह वही अमेरिका है जो एक ओर लोकतंत्र, मानवाधिकार और संप्रभुता की दुहाई देता है, तो दूसरी ओर एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी का दुर्लभ उदाहरण है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन होने तक वाशिंगटन इस लैटिन अमेरिकी देश का संचालन करेगा। यह एक खतरनाक परंपरा है, जिसकी पुनरावृत्ति अमेरिकी महाद्वीप से बाहर होने की आशंका भी बलवती हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि निकोलस मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला में मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से मादुरो को लगातार खलनायक बनाने की कोशिशों में एक वैश्विक तंत्र लगा हुआ था। इस तरह की दोहरी नीतियां केवल विडंबनापूर्ण नहीं, बल्कि वैश्विक शांति के लिये घातक है। वेनेजुएला संकट को केवल मादुरो बनाम अमेरिका के टकराव के रूप में देखना वास्तविकता को सरलीकृत करना होगा। इसमें संदेह नहीं कि मादुरो सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन, दमनकारी नीतियों, चुनावी अनियमितताओं और मानवाधिकार हनन जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। लाखों वेनेजुएलावासी देश छोड़ने को मजबूर हुए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जनता त्रस्त हुई। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि किसी देश की आंतरिक विफलताओं को आधार बनाकर बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को वैध ठहराना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आत्मा के विरुद्ध है। यदि यही मापदंड हो, तो दुनिया के अनेक देशों में बाहरी हस्तक्षेप का अंतहीन सिलसिला शुरू हो सकता है।

रअसल, वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिका की असली चिंता न लोकतंत्र है और न ही मानवाधिकार, बल्कि वहां के विशाल तेल भंडार हैं। वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा देश है और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की अमेरिकी भूख कोई नई बात नहीं है। इराक, लीबिया और अफगानिस्तान इसके उदाहरण हैं, जहां 'लोकतंत्र स्थापना' के नाम पर हस्तक्षेप हुआ, लेकिन परिणामस्वरूप अस्थिरता, गृहयुद्ध और मानवीय संकट ही पैदा हुआ। ट्रंप का यह बयान कि मादुरो को पकड़ने के अभियान का खर्च वेनेजुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, इस पूरे घटनाक्रम की मंशा को बेनकाब करता है। यह कथन स्पष्ट करता है कि यह कार्रवाई न्याय या नैतिकता से नहीं, बल्कि संसाधनों पर नियंत्रण की साम्राज्यवादी सोच से प्रेरित है। किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इस तरह दावा करना उपनिवेशवादी मानसिकता का आधुनिक संस्करण है।इस अमेरिकी कार्रवाई के भू–राजनीतिक परिणाम भी गहरे और दूरगामी होंगे। रूस और चीन ने इसे नियम–आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिये गंभीर खतरा बताया है। मादुरो के आलोचक रहे कुछ अमेरिकी सहयोगी देश भी अब खुलकर चिंता जता रहे हैं। यह संकट वैश्विक ध्रूवीकरण को और तेज कर सकता है। विशेष रूप से चीन को इस घटनाक्रम से अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं, विशेषकर ताइवान पर अमेरिकी आलोचना को कमजोर करने का अवसर मिल सकता है। यदि अमेरिका स्वयं संप्रभुता का उल्लंघन करता है, तो वह दूसरों को किस नैतिक आधार पर संयम की सलाह देगा? वेनेजुएला संकट का एक और चिंताजनक पहलू वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है। तेल उत्पादन और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है। तेल कीमतों में उछाल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर सकता है, विशेषकर विकासशील देशों को। भारत जैसे देशों के लिये यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, जहां ऊर्जा आयात पर निर्भरता अधिक है। यही कारण है कि भारत ने इस घटनाक्रम पर संतुलित रुख अपनाते हुए चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से संवाद व कूटनीतिक समाधान की वकालत की है।भारत का यह दृष्टिकोण न केवल व्यावहारिक है, बल्कि नैतिक रूप से भी अधिक जिम्मेदार है। युद्ध और हस्तक्षेप किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है कि इराक और अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका को अंततः अपमानजनक विदाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वे देश आज भी स्थिरता और शांति से कोसों दूर हैं। युद्ध शुरू करना भले आसान हो, लेकिन शांति और सुशासन स्थापित करना अत्यंत कठिन होता है–यह सत्य अमेरिका बार–बार भूलता रहा है। ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह स्वयं को शांति का अग्रदूत बताता है, लेकिन उसकी हर बड़ी विदेश नीति पहल टकराव और दबाव की राजनीति पर आधारित दिखती है। यह दोहरी मानसिकता न केवल अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की प्रासंगिकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। यदि शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों के अनुसार नियम तोड़ने लगें, तो वैश्विक व्यवस्था अराजकता की ओर बढ़ेगी।वेनेजुएला का संकट पूरी दुनिया के लिये एक चेतावनी है। यह बताता है कि आज भी शक्ति–राजनीति मानवता, शांति और कानून से ऊपर रखी जा रही है। जरूरत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर इस तरह के एकतरफा हस्तक्षेपों का विरोध करे और संवाद, कूटनीति तथा बहुपक्षीय समाधान को प्राथमिकता दे। किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन का निर्णय वहां की जनता को करना चाहिए, न कि विदेशी सेनाओं को। अंततः, अमेरिका को यह समझना होगा कि किसी 'निरंकुश शासक' को हटाना शायद सैन्य शक्ति से संभव हो जाए, लेकिन किसी देश को स्थायी शांति, स्थिरता और समृद्धि देना केवल टैंकों और बमों से नहीं हो सकता। इसके लिये धैर्य, संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान आवश्यक है। यदि अमेरिका वास्तव में वैश्विक शांति का पक्षधर है, तो उसे अपनी दोहरी नीति त्यागनी होगी। अन्यथा, वेनेजुएला जैसी घटनाएँ बार–बार दोहराई जाएंगी और दुनिया एक और अस्थिर, असुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ती जाएगी।

– ललित गर्ग

उत्तर प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026:

12.55 करोड़ से अधिक मतदाताओं की सहभागिता, 6 जनवरी को जारी हुई आलेख्य मतदाता

लखनऊ(संवाददाता)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, शुद्ध और समावेशी बनाने के उद्देश्य से संचालित विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2026 के गणना चरण के मुख्य निष्कर्ष सामने आ गए हैं। 4 नवंबर 2025 से 26 दिसंबर 2025 तक चले इस व्यापक अभियान में राज्य के मतदाताओं की अभूतपूर्व सहभागिता दर्ज की गई। 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची में दर्ज 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाताओं में से 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र जमा कर प्रक्रिया में भागीदारी निभाई।इस अभियान की सफलता के पीछे प्रदेश के सभी 75 जनपदों में तैनात निर्वाचन तंत्र का समन्वित प्रयास रहा। जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, बूथ लेवल अधिकारियों और वॉलेन्टियर्स ने घर–घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया। बूथ लेवल अधिकारियों ने मतदाता सूची में दर्ज प्रत्येक मतदाता तक पहुंच बनाते हुए गणना प्रपत्र वितरित किए और उनके संग्रह के लिए कई बार भ्रमण किया। इस पूरी प्रक्रिया में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और उनके द्वारा नियुक्त 5 लाख से अधिक बूथ लेवल एजेंटों ने भी सक्रिय सहयोग किया, जिससे पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित हो सकी।विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान यह विशेष ध्यान रखा गया कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। इसके लिए राज्यभर में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए और राजनीतिक दलों के साथ कई चरणों में बैठकें आयोजित कर प्रक्रिया की जानकारी साझा की गई। हाशिए पर स्थित वर्गों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांग मतदाताओं और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया, ताकि सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर 6 जनवरी 2026 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। इसके साथ ही दावा और आपत्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है, जो 6 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस अवधि में पात्र मतदाता अपने नाम जोड़ने, अपात्र मतदाताओं के नाम हटाने अथवा प्रविष्टियों में सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राप्त दावों और आपत्तियों का सत्यापन और निस्तारण 27 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, जिसके बाद 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।मतदाता अपना नाम बूथ लेवल अधिकारी के पास उपलब्ध सूची, मोबाइल एप तथा निर्वाचन आयोग की अधिकृत वेबसाइट के माध्यम से देख सकते हैं। जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे आवश्यक अभिलेखों के साथ फॉर्म–6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने पर भी विशेष जोर दिया गया है। 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और अब तक 15 लाख 78 हजार 483 नए मतदाताओं के पंजीकरण के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।मतदाताओं की सुविधा के लिए विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अवधि में जनपद और राज्य स्तर पर संपर्क केंद्र संचालित किए गए, जहां लगभग 62 हजार फोन कॉल्स के माध्यम से नागरिकों की जिज्ञासाओं और समस्याओं का समाधान किया गया। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित विधिक प्रक्रिया और सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना मतदाता सूची से किसी भी नाम का विलोपन नहीं किया जा सकता। आयोग ने दोहराया कि वह पारदर्शी, सहभागी और समावेशी पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि लोकतंत्र की नींव मानी जाने वाली मतदाता सूची और अधिक सुदृढ़ हो

कैबिनेट का बड़ा फैसला:

जीसीसी नियमावली-2025 को मंजूरी, उत्तर प्रदेश को मिलेगा वैश्विक निवेश और रोजगार का नया इंजन

लखनऊ, (संवाददाता)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति–2024 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमावली–2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस नियमावली के लागू होने से प्रदेश में वैश्विक निवेश को बढ़ावा मिलेगा, उच्च स्तरीय सेवाओं का विस्तार होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की संभावनाएं मजबूत होंगी। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित नियमावली के अंतर्गत इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह नियमावली जीसीसी नीति–2024 के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा संशोधित अथवा समाप्त किए जाने तक लागू रहेगी।औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि प्रदेश में निवेश का माहौल लगातार बेहतर हुआ है, जिसके चलते देश–विदेश की बड़ी औद्योगिक इकाइयां और मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए संपर्क कर रही हैं। जीसीसी नीति प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है और इसके अंतर्गत मानक संचालन प्रक्रिया को अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 21 कंपनियों ने जीसीसी के तहत निवेश शुरू कर दिया है, जिससे प्रदेश में व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।नियमावली के अनुसार, जीसीसी किसी भारतीय या विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित की जाने वाली कैप्टिव इकाई होगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, मानव संसाधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और नॉलेज सर्विसेज जैसे रणनीतिक एवं उच्च कौशल आधारित कार्यों का निष्पादन करेगी। इससे उत्तर प्रदेश को ग्लोबल सर्विस डेस्टिनेशन के रूप में नई पहचान मिलेगी।जीसीसी इकाइयों को आकर्षित करने के लिए नियमावली में व्यापक वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। इसके तहत फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट या प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, संचालन व्यय सब्सिडी, पेरोल और भर्ती सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, प्रतिभा विकास एवं कौशल प्रोत्साहन, अनुसंधान और नवाचार प्रोत्साहन के साथ–साथ आवश्यकता के अनुसार विशेष प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जीसीसी इकाइयों को तकनीकी सहायता, इंडस्ट्री लिंकेज सपोर्ट, विनियामक सहयोग, आवेदनों का त्वरित निस्तारण और अनुमोदन व प्रोत्साहन वितरण की सुव्यवस्थित व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी।नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत मिलने वाले सभी प्रोत्साहन, केंद्र सरकार की किसी भी योजना या नीति के तहत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होंगे। किसी भी प्रकार के विधिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार केवल लखनऊ स्थित न्यायालयों का होगा। स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का वितरण वित्त विभाग के प्रचलित नियमों और शासनादेशों के अनुसार किया जाएगा।योगी सरकार के इस निर्णय को उत्तर प्रदेश को ग्लोबल सर्विस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा और दूरगामी कदम माना जा रहा है। जीसीसी नीति और नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में उच्च कौशल आधारित निवेश को नई गति मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

भाजपा ने उत्तर प्रदेश को लूट लिया, 2027 में समाजवादी सरकार बनाकर सामाजिक न्याय का राज स्थापित करेंगे: अखिलेश यादव

लखनऊ(संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भाजपा बेईमानी पर उतर आई है और उसने उत्तर प्रदेश को लूट लिया है। प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है और जनता को गुमराह करने के लिए भाजपा केवल दिखावटी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा मंत्रिमंडल विस्तार जैसे हथकंडों से जनता को धोखा देना चाहती है, लेकिन अब प्रदेश की जनता सब समझ चुकी है। 2027 में भाजपा को सत्ता से हटाने का निश्चय जनता कर चुकी है।मंगलवार को समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। सरकार की नाकामियों के कारण उसका जाना तय है और आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि जनता का भरोसा समाजवादी पार्टी पर है और 2012 से 2017 के बीच समाजवादी सरकार में हुए विकास कार्य आज भी लोगों को याद हैं।अखिलेश यादव ने निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एसआईआर के मामले में निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगा है और भाजपा लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि हर मतदाता का नाम मतदाता सूची में जरूर जुड़वाया जाए और सभी लोग बूथ स्तर पर मजबूती से जुटें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर है और भाजपा के षड्यंत्रों को हर हाल में विफल करना है।उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर प्रदेश में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना की जाएगी, जहां सबको सम्मान और न्याय मिलेगा और प्रदेश का समग्र विकास होगा। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर गोमती रिवरफ्रंट पर महाराजा बिजली पासी की सोने की प्रतिमा स्थापित की जाएगी और सभी महापुरुषों का सम्मान किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी विचारधारा ही समाज को सही दिशा में ले जा सकती है और समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है।

लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा का शुभारंभ, 7 जनवरी से नियमित संचालन, विरासत से रुबरु होंगे देशी-विदेशी पर्यटक

लखनऊ(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मंगलवार को 1090 चौराहे से लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह विशेष पर्यटन बस राजधानी की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों से देशी–विदेशी पर्यटकों और शहरवासियों को परिचित कराएगी। बस 1090 चौराहे से चलकर विधान सभा, हजरतगंज सहित अन्य प्रमुख स्थलों का भ्रमण कराते हुए ऐतिहासिक रेजीडेंसी भवन पहुंचेगी। यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था की गई है, साथ ही उन्हें तुलसी का बीज भी प्रदान किया जाएगा। बस में प्रशिक्षित गाइड तैनात रहेंगे, जो विभिन्न स्थलों के इतिहास, कहानियों और स्थापत्य कला की जानकारी देंगे।अपने संबोधन में पर्यटन मंत्री ने कहा कि लखनऊ का गौरवशाली अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं इसकी पहचान हैं। राजधानी में ऐतिहासिक भवनों और धार्मिक स्थलों की भरमार है। नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने और विदेशी पर्यटकों को लखनऊ की गौरवगाथा से अवगत कराने के उद्देश्य से लखनऊ दर्शन बस सेवा की शुरुआत की गई है। यह डबल डेकर बस 7 जनवरी से नियमित रूप से संचालित की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सेवा राजधानी के पर्यटन विकास की दिशा में एक नई उपलब्धि है, क्योंकि पर्यटन के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और स्थानीय लोगों की आय के नए रास्ते खुलते हैं।पर्यटन मंत्री ने कहा कि लखनऊ के विरासत भवनों से जुड़ा इतिहास, उनकी कहानियां और स्थापत्य कला पर्यटकों के सामने जीवंत रूप में प्रस्तुत की जाएगी। अगले चरण में इस बस सेवा को राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक विस्तारित करने का प्रयास किया जाएगा, जो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पित किया गया है और लखनऊ की समृद्ध विरासत श्रृंखला की एक नई कड़ी है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भविष्य में बसों की संख्या बढ़ाए जाने की भी संभावना जताई गई। उन्होंने लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा की सफल शुरुआत के लिए महानिदेशक पर्यटन राजेश कुमार द्वितीय, उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की सराहना की तथा इस पहल को जन–जन तक पहुंचाने में सहयोग देने वाले मीडिया कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नवाबों के शहर लखनऊ को अपने लजीज व्यंजनों की वैश्विक ख्याति के कारण यूनेस्को की सूची में स्थान प्राप्त है।उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस सेवा प्रतिदिन दो पालियों, सुबह और शाम, में संचालित की जाएगी। यात्री अपनी सुविधा के अनुसार टूर पैकेज का चयन कर सकेंगे। वयस्कों के लिए प्रति व्यक्ति किराया 500 रुपये और 5 से 12 वर्ष आयु के बच्चों के लिए 400 रुपये निर्धारित किया गया है। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के उद्देश्य से 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग पर 10 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है। इच्छुक यात्री यूपीएसटीडीसी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। यात्रा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए टूर गाइड भी उपलब्ध रहेंगे।इस अवसर पर महानिदेशक पर्यटन राजेश कुमार द्वितीय, आशीष कुमार, डॉ. वीरेन्द्र कुमार सहित पर्यटन विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

विकसित भारतह्जी राम जी' से गांव, प्रदेश और देश के समग्र विकास का रोडमैप तैयार: केशव प्रसाद मौर्य

कानपुर नगर(संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि विकसित भारतह्जी राम जी अधिनियम के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया गया है। यह अधिनियम ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, आधुनिक और सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है, जिससे देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त होगा। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के तहत ग्रामीण श्रमिकों को मिलने वाली रोजगार की गारंटी को पहले की तुलना में 25 दिन बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है,।

विशेष अभियान में लखनऊ पुलिस की सख्ती, 6,859 दोपहिया वाहनों का चालान, 163 वाहन सीज

लखनऊ,(संवाददाता) । यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा को लेकर जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट द्वारा दोपहिया वाहनों के विरुद्ध एक विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस व्यापक और प्रभावी अभियान के दौरान नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 6,859 वाहनों का चालान किया गया, जबकि 163 दोपहिया वाहन सीज किए गए।यह विशेष अभियान 05 जनवरी 2026 को पूरे शहर में एक साथ संचालित किया गया। पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के दिशा–निर्देशन तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार के पर्यवेक्षण में कमिश्नरेट के सभी थानों, चौकियों और क्रिटिकल कॉरिडोर क्षेत्रों में बैरियर लगाकर सघन जांच की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य बिना हेलमेट, मॉडिफाइड साइलेंसर, तेज रफ्तार, ट्रिपल राइडिंग, विपरीत दिशा में वाहन चलाने, बिना नंबर प्लेट और बिना वैध दस्तावेज जैसे गंभीर यातायात उल्लंघनों पर रोक लगाना था।शहर के पश्चिमी, मध्य, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणीकृसभी पांच जोनों में पुलिस उपायुक्तों के नेतृत्व में संबंधित सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों की टीमों ने दो शिफ्टों में कार्रवाई की। दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक और शाम 7 बजे से 8 बजे तक प्रमुख बाजार क्षेत्रों, व्यस्त चौराहों, बस स्टैंडों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सघन चेकिंग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ऐसे वाहन पकड़े गए जो बिना हेलमेट चल रहे थे या जिनमें अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर लगे थे। कई वाहनों को वैध कागजात न होने और अवैध परिवर्तन के कारण सीज किया गया।जोनवार कार्रवाई की बात करें तो पश्चिमी जोन में 568 चालान और 35 वाहन सीज किए गए, मध्य जोन में 479 चालान के साथ 2 वाहन सीज हुए, उत्तरी जोन में 327 चालान और 18 वाहन सीज किए गए, पूर्वी जोन में 186 चालान के साथ 2 वाहन सीज हुए, जबकि दक्षिणी जोन में 247 चालान और 3 वाहन सीज किए गए। यातायात पुलिस द्वारा भी अलग से कार्रवाई करते हुए 5,051 चालान और 93 वाहन सीज किए गए। अभियान के दौरान कैसरबाग–हुसैनगंज, नखास, अटल चौक, तेलीबाग चौराहा, 1090 चौराहा, आईटी चौराहा, निशातगंज क्रॉसिंग, अवध चौराहा सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई।पुलिस ने कार्रवाई के साथ–साथ वाहन चालकों को हेलमेट के महत्व, गति सीमा के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति जागरूक भी किया। लखनऊ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन मजबूरी नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध परिवर्तन न कराएं, ट्रिपल राइडिंग से बचें और उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट का उपयोग सुनिश्चित करें।पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर ने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों का पालन कराने की यह पहल एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता है, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और नागरिकों के जीवन की रक्षा करना है। भविष्य में भी लखनऊ पुलिस द्वारा इस तरह के विशेष अभियान और अधिक सख्ती के साथ जारी रहेंगे।

महिलाओं के सवालों पर समाजवादी पार्टी का भरोसा,

अखिलेश यादव से अखिल भारतीय महिला विकास संस्थान के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात

लखनऊ(संवाददाता)। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय, लखनऊ में अखिल भारतीय महिला विकास संस्थान के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। यह प्रतिनिधिमंडल अरविन्द यादव के नेतृत्व में पहुंचा था। संस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और समाज में जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करता है। संस्थान के माध्यम से महिलाओं को सिलाई–कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जाता है और बच्चों की शिक्षा की भी व्यवस्था की जाती है।प्रतिनिधिमंडल में शामिल महिलाओं ने बातचीत के दौरान कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार से उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है। महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो गया है और बेटियों व महिलाओं के लिए जो योजनाएं समाजवादी सरकार के दौरान संचालित थीं, वे अब बंद कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में मिलने वाली कन्या विद्याधन योजना, महिला पेंशन जैसी सुविधाएं समाप्त कर दी गई हैं। आशा ज्योति केंद्रों में कार्यरत महिलाओं को मानदेय नहीं मिल रहा है। पिछड़ी, दलित और मुस्लिम महिलाओं को समाजवादी सरकार के समय जो सहायता मिलती थी, वह भी अब खत्म हो चुकी है।महिलाओं ने वर्ष 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि उन्हें अखिलेश यादव पर पूरा भरोसा है। प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं के हित में पुनः सभी कल्याणकारी योजनाएं लागू की जाएंगी और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित होगी।अखिलेश यादव ने प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिलाया कि समाजवादी सरकार बनने पर महिलाओं की सभी जायज मांगें पूरी की जाएंगी। उन्होंने पिछली समाजवादी सरकार के कार्यों को याद दिलाते हुए कहा कि उस समय महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 वूमेन पावर लाइन शुरू की गई थी, 108 और 102 एंबुलेंस सेवाएं, डायल 100, मुफ्त इलाज की व्यवस्था की गई थी।

मादक पदार्थों के खिलाफ लखनऊ पुलिस का बड़ा अभियान, पांच जोनों में 30 स्थानों पर छापेमारी, 6 गिरफ्तार

लखनऊ,(संवाददाता) । मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह अंकुश लगाने के उद्देश्य से लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने शहर भर में एक व्यापक और सघन विशेष अभियान चलाया। 05 जनवरी 2026 को संचालित इस अभियान के तहत शहर के सभी पांच जोनों में एक साथ कार्रवाई करते हुए 30 संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान मादक पदार्थों के अवैध कारोबार से जुड़े 100 से अधिक लोगों को चिन्हित किया गया, 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और कुल 5678 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। इस कार्रवाई से नशे के अवैध नेटवर्क में हड़कंप मच गया है।नगरवासियों की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर के दिशा–निर्देशन और संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार के निकट पर्यवेक्षण में यह विशेष सघन अभियान संचालित किया गया। अभियान के लिए एंटी नार्कोटिक्स टीम, स्वाट टीम और संबंधित थानों की संयुक्त टीमें गठित की गईं। गहन अभिसूचना संकलन के बाद भरवारा क्रॉसिंग, फन मॉल, मड़ियांव पुल, सिंगापुर मॉल सहित अन्य संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया, जहां मादक पदार्थों की बिक्री की शिकायतें सामने आ रही थीं।अभियान के दौरान अपर पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस आयुक्तों के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने एक साथ छापेमारी करते हुए थाना विभूतिखंड, गोमतीनगर, गाजीपुर और मड़ियांव क्षेत्र में चार अभियोग दर्ज किए। इन मामलों में छह अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान मादक पदार्थों की आपूर्ति से जुड़े अन्य व्यक्तियों और संभावित ठिकानों के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मदद से सामने आए नए नामों और स्थानों को लेकर पुलिस द्वारा विस्तृत जांच की जा रही है।लखनऊ पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में मादक पदार्थों के सेवन और बिक्री से जुड़ी किसी भी अवैध गतिविधि को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह अभियान केवल एक दिन की कार्रवाई नहीं बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसके तहत भविष्य में भी ऐसे सभी संभावित स्थानों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नशे से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समाज को इस गंभीर सामाजिक बुराई से मुक्त किया जा सके।

काग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर सीतापुर की अनुप्रिया वर्मा और नेहा चौधरी समर्थकों संग काग्रेस में शामिल

लखनऊ(संवाददाता)। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की नीतियों और उसकी समावेशी विचारधारा में आस्था जताते हुए तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा देश के आमजन के मुद्दों पर सदन से लेकर सड़क तक किए जा रहे संघर्षों से प्रेरित होकर जनपद सीतापुर की अनुप्रिया वर्मा और नेहा चौधरी ने अपने–अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। यह कार्यक्रम सांसद राकेश राठौर के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय, लखनऊ में आयोजित किया गया, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की उपस्थिति में दोनों नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा।इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस में शामिल हुए सभी नए सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें पार्टी की तिरंगा पट्टिका पहनाई और सदस्यता कार्ड प्रदान कर विधिवत रूप से कांग्रेस परिवार में शामिल किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और आमजन के अधिकारों की आवाज उठाती रही है और आज बड़ी संख्या में युवाओं तथा सामाजिक रूप से सक्रिय लोगों का पार्टी से जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि जनता का भरोसा कांग्रेस की नीतियों और नेतृत्व पर बढ़ रहा है।कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ज्वाइनिंग प्रभारी नितिन शर्मा भी मौजूद रहे। इनमें प्रमुख रूप से आयुष कुमार, सूरज कुमार, अमित जायसवाल, प्रेम शंकर राठौर, सर्वेश वर्मा, मोहम्मद अकरम, गुरप्रीत सिंह, रियाज अहमद, शमशाद अली, नितेश कुमार मसीह, विनोद राठौर, धर्मेंद्र राठौर, साहिल राठौर, आनंद राठौर, अनुराग राठौर, मोनू गोस्वामी, विशाल गोस्वामी, अरविन्द साहू, नरेन्द्र यादव, विजय साहू, राजाराम साहू, निशांत मिश्रा, मोहिन्दर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे।कांग्रेस में शामिल हुए नए सदस्यों ने कहा कि वे कांग्रेस की विचारधारा, सामाजिक समरसता और आमजन के मुद्दों को लेकर किए जा रहे संघर्षों से प्रेरित होकर पार्टी से जुड़े हैं ।और आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे।

शिप्रा अवस्थी बनी लखीमपुर-खीरी मनरेगा बचाओ संग्राम को-आर्डिनेटर! संगठनात्मक स्तर पर अभियान को मजबूती देने का लिया कांग्रेस ने निर्णय

लखीमपुर–खीरी।अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर चलाए जा रहे ष्मनरेगा बचाओ संग्रामष अभियान को उत्तर प्रदेश में मजबूती देने के लिए कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी क्रम में लखीमपुर–खीरी जिले की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री शिप्रा अवस्थी को इस अभियान का जिला को–आर्डिनेटर नियुक्त किया गया है।कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के मुताबिक, प्रदेश के सभी जनपदों में जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटियों के सहयोग हेतु वरिष्ठ कांग्रेस एक्टिविस्टों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के कारण कमजोर पड़ रही मनरेगा योजना को बचाने के लिए व्यापक जन–आंदोलन खड़ा करना है।कांग्रेस नेत्री शिप्रा अवस्थी की नियुक्ति पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया है कि उनके नेतृत्व में जनपद में मनरेगा बचाओ संग्राम को नई मजबूती मिलेगी। ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोआर्डिनेटर चौपालों, जनसभाओं और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता को मनरेगा से जुड़े मुद्दों से अवगत कराएंगे और मजदूरों के अधिकारों की आवाज बुलंद करेंगे।नवनियुक्त जिला कोआर्डिनेटर शिप्रा अवस्थी ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ इस अभियान को आगे बढ़ाएगी उन्होंने मनरेगा से जुड़े हर वर्ग की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ने का संकल्प लिया।

नगर पालिका परिषद लखीमपुर अधिशासी अधिकारी ने वार्ड का किया निरीक्षण

लखीमपुर–खीरी। नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी संजय कुमार ने मंगलवार को नगर पालिका परिषद के अंतर्गत मोहल्ला हाथीपुर दुर्बल आश्रम वार्ड का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी ने वार्ड में सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। उसके बाद ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान सभासद प्रतिनिधि किशोरी लाल, अवर अभियंता जितेंद्र वर्मा तथा सफाई नायक उपस्थित थे। वार्ड में सबसे बड़ी समस्या यह भी पाई गई की कुछ लोगों द्वारा प्लॉट खरीदकर उसे खाली छोड़ दिया है। जिसका परिणाम होता है खाली प्लाटों में लोग कूड़ा आदि डालकर गैर जिम्मेदाराना कार्य करते हैं जिससे ज्यादातर कूड़ा पड़ा रहता है। जिसको देखते हुए अधिशासी अधिकारी ने कडी आपत्ति करते हुए कहा ऐसे लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है कि वे प्लॉट की बाउंड्री करवा लें, अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा।

आमने-सामने हुई बाइकों की भिड़ंत

धौरहरा खीरी ———सोमवार शाम लगभग 5 बजे सिसैया ढखेरवा हाइवे पर सिसैया बाजार के पास कोहरे व भयानक ठंड के कारण दो बाईकों की आमने सामने भिड़ंत होने से तीन लोग घायल हो गए जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सी एच सी धौरहरा में भर्ती कराया गया।

प्राप्त विवरण के अनुसार सोमवार शाम लगभग 5 बजे धौरहरा की तरफ से बाइक पर सवार होकर ईसानगर थाने जा रहे आरक्षी विकल कुमार 30 वर्ष व महिला आरक्षी सोनिया सागर 25 जाते वक्त व सिसैया चौराहे पर बाइक एजेसी में काम करके बाइक पर सवार होकर धौरहरा के मोहल्ला शुक्ला वार्ड निवासी 26 वर्षीय शिवम् मिश्रा पुत्र आनंद किशोर की बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत में सभी लोग घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए सी एच सी धौरहरा में भर्ती कराया गया। समाचार प्रेषण तक चिकित्सकों ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

नगर पालिका आपके द्वार अभियान का नीलकंठ मैदान से शुभारंभ

(हरिशंकर मिश्र)

गोला / लखीमपुर खीरी। मंगलवार 06 जनवरी मो० तीर्थ स्थित नीलकण्ठ मैदान में आम जनमानस की समस्याओं के निराकरण के लिए नगर पालिका परिषद गोला के तत्वावधान में कैम्प का आयोजन किया गया जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि एसडीएम गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी,तहसीलदार भीमचन्द एवं पालिकाध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने फीता काटकर किया।नगर पालिका आपके द्वार अभियान में उपस्थित आमजन को सम्बोधित करते हुए कहा कि,ष नगर की सम्मानित जनमानस को दफ्तरों के चक्कर नही लगाने पडे इसके लिए नगर पालिका आपके द्वार अभियान चलाया गया है।हम सभी वार्डो में जाएंगे और निरूशुल्क राशनकार्ड, पेंशन, विद्युत विभाग और नगर पालिका की समस्याओं का निस्तारण करेंगे।एस डी एम प्रतीक्ष त्रिपाठी ने कहा,ष पालिकाध्यक्ष के इस अभियान से सभी विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा समस्याएं सुनकर उसका निराकरण करेंगे।नगर पालिका आपके द्वार अभियानका कैम्प वार्ड 06,19व 10 तीनों वार्डों से विद्युत विभाग की 06, वृद्धावस्था पेंशन की 41,दिव्यांग जनों की 03, विधवा पेंशन की 03 ,राशनकार्ड की 163 प्रार्थना पत्र आए।07 जनवरी को कुम्हारन टोला स्थित गौशाला में प्रातरू 10 बजे से 04 बजे तक कैम्प रहेगा।इस अवसर पर सभासद राजेश अवस्थी, हर्ष अवस्थी, आनंद किशोर गिरि भोली,जिला महामंत्री ओबीसी मोर्चा विनोद स्वर्णकार,लेखाकार मोहित अवस्थी,एस आई संदीप वर्मा, वरिष्ठ लिपिक अमित श्रीवास्तव, जेई सिविल अनिल कुमार यादव,जेई जलकर आदर्श मिश्रा,विद्युत विभाग से जेई धर्मेन्द्र चौधरी, टीजी टू मनीष सिंह, जितेन्द्र सिंह, खाद्य एवं रसद विभाग ऋषभ श्रीवास्तव अजय,दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग अजय कुमार पर्वेक्षक, एकता सिंह कार्यालय सहायक ,नगर पालिका से श्रवण कुमार मिश्रा, ऋषि कुमार, करुणाकान्त ,आशोक कुमार मिश्रा, विमलेश वर्मा आदि मौजूद रहे।

डिजिटल हाउस अरेस्ट के नाम पर 54 लाख की साइबर ठगी, चार आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ।साइबर अपराधियों ने रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी राजेंद्र प्रकाश वर्मा को "डिजिटल हाउस अरेस्ट" का डर दिखाकर 54 लाख रुपये की ठगी कर ली। ठगों ने खुद को एटीएस और एनआईए का अधिकारी बताते हुए वीडियो कॉल के माध्यम से वारदात को अंजाम दिया।आरोपियों ने गिरफ्तारी का भय दिखाकर पीड़ित को कथित तौर पर डिजिटल हाउस अरेस्ट में रखा और अलग–अलग खातों में 54 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। मामले की जांच के बाद साइबर क्राइम टीम ने चार आरोपियोंकृमो. सूफियान, मो. आजम, आरिफ इकबाल और उजैर खानकृको गिरफ्तार किया है।

डीसीपी क्राइम कमलेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी संगठित गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपी उजैर खान लखनऊ में नीट (छम्म्ज) की कोचिंग कर रहा था, जबकि ठगी की रकम थाईलैंड में बैठे मास्टरमाइंड तक पहुंचाई जाती थी।पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ठगी की रकम को आगे ट्रांसफर करने के बदले मोटा कमीशन लेते थे। साइबर क्राइम टीम अब गिरोह के विदेशी नेटवर्क और मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है।पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात वीडियो कॉल, खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताने वाले फोन कॉल या डिजिटल हाउस अरेस्ट जैसे दावों से सतर्क रहें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं।

मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन, डीएम ने जनमानस के लिए किया जारी, BLO और सुपरवाइजर हुए सम्मानित

लखीमपुर खीरी, 06 जनवरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर प्रक्रिया के तहत जनपद मुख्यालय के मतदान केंद्र गुरुनानक इंटर कॉलेज में मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारीध्डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने डिप्टी डीईओध्एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह के साथ मतदान केंद्र के सभी बूथों की ड्राफ्ट सूची जनमानस के अवलोकन के लिए जारी की। कार्यक्रम का सफल संयोजन ईआरओध्एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह ने किया।

कार्यक्रम के दौरान डीएम ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच बूथ लेवल ऑफिसर (ठस्व) और तीन सुपरवाइजर को माला पहनाकर और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। डीएम ने कहा कि इस अभियान में जुड़े सभी कर्मियों ने दिन–रात मेहनत कर मतदाता सूची को त्रुटिरहित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर युवा फॉर्म छह भरकर मतदाता बनें, क्योंकि मतदान केवल अधिकार नहीं, बल्कि देश सेवा का पहला कदम है। प्रत्येक योग्य मतदाता का मतदान हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है और इसे पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ड्राफ्ट सूची के प्रकाशन के दौरान नागरिकों को अपने नाम, पता और अन्य विवरणों में सुधार के लिए पूरा अवसर दिया गया है। डीएम ने सभी कर्मियों और युवा प्रतिभागियों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया।एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि यह प्रक्रिया केवल प्रशासनिक काम नहीं, बल्कि लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने का अहम कदम है। उन्होंने बूथ लेवल अधिकारियों और सुपरवाइजरों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि दिन–रात किए गए प्रयास से मतदाता सूची त्रुटिरहित तैयार की गई है।इस दौरान 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के लिए बीएलओ द्वारा मैन्युअल और ऑनलाइन फॉर्म छह भरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम में तहसीलदार मुकेश कुमार, स्थानीय नागरिक, बूथ लेवल ऑफिसर, सुपरवाइजर, जनप्रतिनिधि और युवा छात्र–छात्राएं शामिल हुए।ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे–आपत्तियां 06 जनवरी से 06 फरवरी तक, डीएम ने राजनीतिक दलों को दी प्रारूप प्रकाशन की प्रतियां

जिले में महिला मतदाता 10.75 लाख पार, लखीमपुर विधानसभा में सर्वाधिक मतदाता पंजीकत

लखीमपुर खीरी 06 जनवरी। मंगलवार को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्ट्रेट स्थित अटल सभागार में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने राष्ट्रीय और राज्यीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का संचालन एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। इस अवसर पर डीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचक सूची के प्रारूप प्रकाशन की प्रतियां प्रदान कीं।

जिले में महिला मतदाताओं की संख्या 10.75 लाख पार

घ्प्रारूप प्रकाशन के आंकड़ों के अनुसार, जनपद की आठों विधानसभाओं (पलिया, निघासन, गोला गोकर्णनाथ, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपुर, कस्ता और मोहम्मदी) में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या 13,08,140 और महिला मतदाताओं की संख्या 10,75,881 है। वहीं, जिले में कुल 49 थर्ड जेंडर मतदाता भी पंजीकृत हैं। सर्वाधिक मतदाता लखीमपुर विधानसभा (3,22,931) में हैं।ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावेदृआपत्तियां 06 जनवरी से 06 फरवरी तक कराए दर्ज

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद नागरिकों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर 06 जनवरी से 06 फरवरी 2026 तक मिलेगा। इस अवधि में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधार या स्थानांतरण के लिए आवेदन किया जा सकता है। जिन युवाओं की 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी है या होने वाली है, उन्हें फॉर्म–6 का उपयोग करना होगा। फॉर्म–6 के साथ अनुलग्नक–4 (घोषणा पत्र) और आवश्यक अभिलेख संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।निर्वाचक सूची में पहले से दर्ज मतदाताओं में किसी प्रविष्टि में सुधार या एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण के लिए फॉर्म–8 का प्रयोग किया जाएगा। मतदाता सूची से नाम अपमार्जित करने के लिए फॉर्म–7 का उपयोग होगा। प्रवासी भारतीय, जो विदेश में रहते हैं, उन्हें फॉर्म–6ए के साथ आवश्यक अभिलेख जमा कराना होगा।

पूर्व सूची में नाम नहीं होने वाले मतदाताओं के लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश

यदि किसी नागरिक का नाम या उनके माता–पिताध्दादा–दादी का नाम पूर्व विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण–2003 की निर्वाचक सूची में शामिल नहीं है, तो उसे अपने नामांकन के लिए आवश्यक अभिलेख संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी को जमा करना होगा।इसमें केंद्रध्राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 01. 07.1987 से पहले जारी सरकारी प्रमाण पत्रध्पहचान पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्डधविश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकध्शैक्षणिक प्रमाण पत्र,सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसीध एससीध्एसटी या जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में दर्ज अभिलेख, राज्यध स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र शामिल हैं। वही आधार के लिए आयोग के पत्र संख्या 23 ध 2025 – ईआरएस ध खंड द्यद्य दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक प्प) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार ।

पत्रकारों की पेंशन व सुरक्षा पर विधायक राजेश्वर सिंह का आश्वासन, मीडिया सेंटर में हुआ संवाद

लखनऊ।लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारों की सामाजिक, आर्थिक एवं पेशेवर चुनौतियों को लेकर सरोजिनी नगर विधायक राजेश्वर सिंह ने एक बार फिर संवेदनशील और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने का परिचय दिया। लाल बहादुर शास्त्री भवन एनेक्सी स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पत्रकारों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना।उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति (पुनर्गठित) के संयोजक प्रभात त्रिपाठी के आमंत्रण पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकारों ने विधायक राजेश्वर सिंह का गर्मजोशी एवं उत्साहपूर्वक स्वागत किया। स्वागत उपरांत संयोजक प्रभात त्रिपाठी ने पत्रकारों से जुड़े वर्षों से लंबित मुद्दोंकृ पत्रकार पेंशन व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा तथा पत्रकार सुरक्षा कानूनकृको क्रमवार विधायक के समक्ष रखा।पत्रकारों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हुए विधायक राजेश्वर सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पत्रकार समाज की आवाज होते हैं और उनके हितों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पत्रकार पेंशन के मुद्दे पर वह स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे और एक ठोस प्रस्ताव उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री पत्रकारों की भूमिका और योगदान को भली–भांति समझते हैं और इस दिशा में सकारात्मक निर्णय अवश्य लिया जाएगा।विधायक ने कहा कि पत्रकारों की समस्याएं केवल मांग नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती से सीधे तौर पर जुड़ा विषय हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि वह पत्रकारों के हर न्यायोचित मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर शासन स्तर तक निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उनका यह आश्वासन पत्रकार समुदाय के लिए नई उम्मीद और विश्वास का संदेश लेकर आया।स्वागत समारोह के दौरान विधायक राजेश्वर सिंह को अंगवस्त्र पहनाकर, पुष्पगुच्छ एवं श्रीमद्भगवद्गीता भेंट कर सम्मानित किया गया। विधायक ने भी इस अवसर पर सरोजिनी नगर की विकासात्मक उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक "प्रगति की डगरकृसरोजिनी नगर" एवं डायरी पत्रकारों को वितरित की।

कार्यक्रम के अंत में उपस्थित पत्रकारों ने विधायक को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में पत्रकार पेंशन तथा पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। यह मुलाकात पत्रकार समुदाय के लिए न केवल संवाद का मंच बनी, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का शुभ संकेत भी साबित हुई।इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार उमेश चंद मिश्रा, सुशील दुबे, अजय वर्मा, अजीत कुमार सिंह, रवि शंकर उपाध्याय, संजय धीमान, प्रदीप उपाध्याय, जेड. ए. सिद्दीकी, अविनाश राय, राजेश मिश्रा, अमन अग्रवाल, समीर (शाहनवाज), उमाकांत बाजपेई, शशिनाथ दुबे, त्रिनाथ शर्मा, अरुण शर्मा सहित अनेक पत्रकार उपस्थित रहे।

सेमीकंडक्टर निवेश को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन, पीलीभीत से वाराणसी तक विकास योजनाओं पर कैबिनेट की मुहर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक

में प्रदेश के औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने वाले कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार की जनवरी 2024 में लागू सेमीकंडक्टर नीति के तहत बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से घ्3,000 करोड़ या उससे अधिक के निवेश पर विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 को स्वीकृति प्रदान की गई।

उन्होंने बताया कि अमेरिका, यूरोप, जापान और ताइवान जैसे देशों में सेमीकंडक्टर निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है और अब उत्तर प्रदेश को इस उभरते उद्योग का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में योगी सरकार ने केस–टू–केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। इसके तहत सेमीकंडक्टर इकाइयों को ब्याज सब्सिडी, कर्मचारी लागत की प्रतिपूर्ति, 10 वर्षों तक नेट एसजीएसटी में छूट, उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 100 प्रतिशत ईपीएफ प्रतिपूर्ति (अधिकतम घ्2,000 प्रतिमाह), जल मूल्य में छूट तथा 10 वर्षों तक प्रति यूनिट घ्2 बिजली दर में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नीति का उद्देश्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर सृजित करना है।

पीलीभीत में बनेगा आधुनिक बस स्टेशन

कैबिनेट बैठक में पीलीभीत के टनकपुर रोड स्थित मुख्यालय के पास एक आधुनिक बस स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। यह बस स्टेशन राजस्व विभाग की 1.317 हेक्टेयर भूमि पर बनाया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को 30 वर्षों की लीज पर दिया जाएगा, जिसे आगे 90 वर्षों तक बढ़ाया जा सकेगा। इस बस स्टेशन के निर्माण से उत्तराखंड और नेपाल जाने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य दो वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वाराणसी में बनेगा 500 बेड का मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल

कैबिनेट ने शिव प्रसाद गुप्ता एसएसपीजी मंडलीय जिला चिकित्सालय, वाराणसी परिसर में स्थित 11 जर्जर एवं अनुपयोगी भवनों को ध्वस्त कर 500 शैय्या वाले मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण को मंजूरी दी है। यह अस्पताल 315 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत से बनेगा, जिसका निर्माण कार्य चार वर्षों में पूर्ण किया जाएगा। परियोजना की 60 प्रतिशत लागत केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। इससे पूर्वांचल क्षेत्र के मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

खेल विभाग में भर्ती नियमों में संशोधनकैबिनेट ने खेल विभाग में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया में संशोधन को स्वीकृति दी है। विभाग में कुल 18 पद स्वीकृत हैं। अब दो–तिहाई पद पदोन्नति के माध्यम से और एक–तिहाई पद अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों (ओलंपिक, एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स) से भरे जाएंगे। इस निर्णय से अनुभवी अधिकारियों के साथ–साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी अवसर मिलेगा।

कानपुर में 37वीं वाहिनी पीएसी के नए आवास

कैबिनेट ने कानपुर स्थित 37वीं वाहिनी पीएसी के पुराने एवं जर्जर आवासीय भवनों को ध्वस्त करने और उनके स्थान पर टाइप–वन स्पेशल के 108 नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है। इससे पीएसी जवानों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

वाराणसी में खुलेगा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ऑफ–कैंपस

कैबिनेट ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, गांधीनगर (गुजरात) के वाराणसी में ऑफ–कैंपस की स्थापना के लिए 50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। यह भूमि तहसील राजा तालाब क्षेत्र में स्थित है, जिसे पशुधन विभाग से 99 वर्षों की लीज पर विश्वविद्यालय को दी जाएगी। इस कैंपस की स्थापना से फॉरेंसिक साइंस, साइबर अपराध और आपराधिक जांच के क्षेत्र में प्रदेश को शैक्षणिक और तकनीकी मजबूती मिलेगी।

खेत मजदूर संगठन ने ब्लाकों पर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन

अयोध्या। वामपंथी दलों से जुड़े खेत मजदूर संगठनों, संयुक्त किसान मोर्चा एवं ट्रेड यूनियनों ने मंगलवार को राष्ट्रीय आह्वान पर जिले के विभिन्न ब्लाक कार्यालयों पर प्रदर्शन कर खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा विगत 03 जनवरी को मिर्जापुर जिले में भाकपा (माले) राज्य सचिव सुधाकर यादव, राज्य कमेटी सदस्य जीरा भारती व अन्य कार्यकर्ताओं को गैरकानूनी तरीके से गिरफ्तार कर फर्जी केस में जेल भेजने की कार्यवाही को योगी सरकार की अलोकतांत्रिक और दमनकारी बताते हुए कठोर शब्दों में निंदा की और अविलंब बिनाशर्त रिहा करने की मांग की गई। ज्ञापन में "विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन" को तत्काल निरस्त कर मनरेगा कानून को और सार्वभौमिक बनाते हुए दो सौ दिन काम और 600 रुपए मजदूरी की गारंटी करने, संगठितध असंगठित मजदूरों के लिए गुलामी का नया दस्तावेज चारों श्रम संहिता को निरस्त करने, बिजली विभाग का निजीकरण बंद करने, स्मार्ट मीटर को लगाने से रोकने तथा 200 यूनिट बिजली फ्री देने, बुल्डोजर चलाकर गरीबों को उजाड़ने से रोकने तथा प्रत्येक गरीब को वास – आवास के लिए पांच डिसमिल जमीन देने, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा ग्रामीण गरीबों को दिए जा रहे कर्ज के लेन देन में आरबीआई गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा दो लाख तक के कर्ज माफ करने की मांग की गई है। पूरा ब्लाक में खेत मजदूर संगठन के प्रांतीय महामंत्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह, भाकपा (माले) राज्य कमेटी सदस्य राजेश वर्मा, शिवराम, उत्तम कुमार, मया ब्लाक में भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य राम भरोस, मजदूर नेता लक्ष्मण, मोहन यादव, राजबली यादव, तारुन ब्लाक में माकपा जिला सचिव अशोक यादव, संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक मयाराम वर्मा, भाकपा माले नेता उमाकांत विश्वकर्मा, खेत मजदूर यूनियन के जिला मंत्री माता बदल, किसान नेता बाबूराम यादव, बीकापुर तहसील में किसान सभा के जिला सचिव मयाराम वर्मा, वरिष्ठ नेता शेख मोव इशहाक, वरिष्ठ अधिवक्ता राम तेज वर्मा आदि नेताओं ने प्रदर्शन का नेतृत्व किया और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा।

डीएम ने मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ

अयोध्या। भारत निर्वाचन आयोग अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 के अवसर पर मतदाता रजिस्टेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ जिलाधिकारीधजिला निर्वाचन अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे द्वारा झुनझुनबाला परास्नातकोत्तर महाविद्यालय अयोध्या में किया गया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि सभी नये युवा, जिन्होंने 18 वर्ष हो गये है और अभी तक अपना मतदाताध्एपिक आई0डी0 के लिए आवेदन नहीं किया है तो मतदाता सेवा पोर्टल अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 की वेबसाइड पर जाकर आनलाइन आवेदन कर सकते है और ऑनलाइन पर अपनी सूची भी देख सकते है। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए उनके नजदीकी पोलिंग बूथ पर बूथ लेवेल अधिकारियों द्वारा फार्म–6 नाम जोड़ने का, फार्म–7 नाम कटवाने का तथा फार्म–8 संशोधित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जनपद के बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने क्षेत्रों में निर्वाचन संबंधित कार्य को निधारित समयावधी एवं पारदर्शिता के साथ संपादित करना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के कार्य को तेजी व अच्छे तरह से करने पर बी0एल0ओ0 को सम्मानित किया तथा 18 वर्ष हो गये युवाओं को फार्म 6 उपलब्ध कराया। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनिरुद्ध प्रताप सिंह, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सदर, संबंधित बी०एल०ओ० व सुपरवाइजर तथा स्कूल के युवा बच्चे उपस्थित रहे।

डूंग जी महाराज की पुण्यतिथि पर संतों का जुटान

प्रयागराज। सेक्टर छह स्थित श्री डूंग जी महाराज संस्थान (भूरा मठ) में मंगलवार को स्वामी हरीश्वरानंद तीर्थ जी की पुण्यतिथि मनाई गई। यहां दंडी सन्यासियों का जुटान हुआ। उन्हें भूरा मठ की तरफ से प्रसाद और कंबल वितरित किया गया। हजारों सन्त महापुरुषों सहित जरूरतमंद लोगों में कम्बल का पुनः वितरण हुआ। दंडी समाज के प्रवक्ता विद्यामार्तंड अरविंद स्वामी जोशी ने बताया कि प्रतिवर्ष माघ मास में उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इस लिहाज से मंगलवार को भी दंडी समाज से जुड़े संतों एवं आमजनमानस के लिए अन्नक्षेत्र का संचालन किया गया। इस दौरान सभी को प्रसाद के साथ कंबल भी वितरित किए गए। इसके बाद दक्षिणा देकर संतों को विदा किया गया।मठ के व्यवस्थापक आचार्य आदर्श मिश्रा और निखिल के देखरेख में हजारों लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। अरविंद स्वामी ने बताया कि भूरा मठ के संस्थापक ने ताउम्र गोसेवा की। यह सुखद पल है कि उनकी स्मृति में संगम की रेतीली धरा पर संतों का सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि स्वामी डूंग जी भी माघ मास में यहां संतों की सेवा करने आते थे। उन्होंने संतों की सेवा के लिए ही अपनी काफी सम्पत्ति भी न्योछावर कर दी। अरविंद स्वामी ने बताया कि पूरे माघमास नित्य विशाल अन्नक्षेत्र शिविर का संचालन किया जाएगा।

कांग्रेस की एसआईआर निगरानी कमेटी में प्रदीप मिश्रा अंशुमन भी

प्रयागराज। एसआईआर की गतिविधियों के संबंध में स्थानीय कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने हेतु भारतीय चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में कराये जा रहे एसआईआर की जिला स्तरीय निगरानी हेतु अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अनुमति के बाद उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसजनों की जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। तत्क्रम में जनपद प्रयागराज (इलाहाबाद) में सांसद उज्जवल रमण सिंह, पूर्व विधायक श्याम सूरत उपाध्याय तथा महानगर कॉंग्रेस कमेटी प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप मिश्र अंशुमन को उत्तरदायित्व दिया गया है स इन वरिष्ठ नेताओं को प्रयागराज की जिम्मेदारी मिलने से कार्यकर्ताओं में अपार खुशी है। लोगों में आशा एवं विश्वाश प्रगाढ़ हुआ है कि बीजेपी के कुचक्र से जो वोट साजिश के तहत काटे जा रहे है उस पर रोक लगेगी अब कोई वोटर बनने से वंचित नहीं हो पाएगा। बधाई देने वालों में प्रमुख रूप से राजेश राकेश, लल्लन पटेल, दिवाकर भारतीय, विनय पाण्डेय, अनूप सिंह, मोहम्मद इरफान, मंजू मौर्य, विष्णु कांत पांडे, रचना पाण्डेय, श्वेता श्रीवास्तव, अजेंद्र गौड़, अब्दुल कलाम आजाद, सौरभ चौधरी, शुभम शुक्ला, चंद्र विशाल वार्ष्णेय, राहुल यादव, राजीव रंजन, राजेंद्र मिश्रा समीर, मुन्नू केसरवानी उपस्थित रहे।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, ४० वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी २/३७६ रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ० प्र० से प्रकाशित।

सम्पादक
आरती पाण्डेय
ek-
9807059191- 9026560178
Email-
adbhutsamachar@gmail.com
adbhutsamachar@hotmail.com

सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।